

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : ०२ मार्च, 2016

विषय: श्रीमती सुमति जखमोला, नामिका अधिवक्ता (फौजदारी), जिला हरिद्वार का कार्यकाल बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०-02 ना०वा०/XXXVI(1)/2014-01 ना०वा०-बी०/2006 दिनांक 17.10.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती सुमति जखमोला, नामिका अधिवक्ता (फौजदारी), हरिद्वार का कार्यकाल दिनांक 17.10.2015 से अग्रेत्तर अग्रिम आदेशों तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नहीं है। राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के नामिका अधिवक्ता (फौजदारी), हरिद्वार के पद पर श्रीमती जखमोला की आबद्धता समाप्त कर सकती है अथवा श्रीमती जखमोला भी इस आबद्धता को किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। श्रीमती जखमोला इस आशय का सहमति प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इस शर्त में कोई आपत्ति नहीं है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

०१-जा.व-८०२

संख्या: /XXXVI(1)/2016-01 ना०वा०-बी०/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- जिला न्यायाधीश/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 3- सम्बन्धित अधिवक्ता।
- 4- एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव